सार्वजानिक टैलीफोन प्रदान करने के लिए लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1994-95	50000	47,604
1995-96	105000	31,496
1996-97	75000	56,719

(ग) पूवोक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य और प्राप्ति के बीच का अंतर निम्नानुसार दिया गया हैं:

1994-95	2396
1995-96	73504
1996-97	18281

वर्ष 1997-98 के लिए 83000 का लक्ष्य निर्धारित हैं।

गुजरात में बुनकरों को न्यूनतम वेतन

*314. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि कच्छ में हथकरघा निगम के बुनकरों को उच्चतम न्यायाल के निर्णय के बावजूद भी न्यूनतम वेतन नही मिल रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को उन्हे औद्योगिक मजदूरों के समतुल्य मानने का निर्देश दिया हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के संबंध में श्रम मंत्रालय के स्थायी आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया हैं?

वस्त्र मत्री (श्री आर.एल.जालप्पा) : (क) से (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया हैं कि उन्हे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी नहीं हैं। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचित किया हैं कि गुजरात सरकार द्वारा हथकरघों में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की गई हैं। यद्यपि इस मामले में विस्तृत सूचना इकत्रित की जा रही हैं।

(ड.) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत गुजरात सरकार अपने क्षेत्र में रोजगार के सम्बन्ध में अधिनियम प्रावधानो को कार्यान्वित तथा लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार द्वारा अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्तन मशीनरी की भी स्थापना की गई हैं। श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया हैं कि प्रवर्तन मशीनरीं की प्रभावकारिता में सुधार लायें।

Working of local bodi«a

*315.DR.D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleas-e-d to state:

(a) whether the working of local bodieas in the States is being examined by Govrnement

;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, steps taken to check and identify drawbacks in tneir fuuctioniag; and

(d) the Steps proposed to be taken to streamline the system?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENI (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) to (d) Yes, Sir. Tne wonting of the ranchayati Raj institutions in the country is reviewed from time to time in the meetinse of concerned Panchayati Raj Ministers and Secretaries heid at the national level. A National Committee of Panchayat Ministers under the Chairmanship of Minister of Rural Areas and Employment has been constituted for the purpoise. Several suggestions have been made to the States/UTs to streamline the functioning of Panchayati Raj system. A Southern Regional Conference of the Chairpersons of Zila Parishads at NIRD, Hyderabad was held in June, 1997, to know the working of the P.R. bodies in all the selected Southern States, More recently, the Chief Ministers' Conference was held on 2-8-1997 at. New Delhi to review the working of the Panchayati Raj Institutions; where the outstand'n"; issues like devolution of powers/functions and responsibilities upon PRIs, setting u,p of District Planning Committees and implementaticn of Reports of the Stata Finance Commissions and training to PRIs were discussed; and the Conference recommended to set up two Committees; (a) the Committee of the Paochayats and the Tribal Development Ministers of the eight States from the areas covered under Schedule V of the Constitution, under the Chairmanship of Minister (RA&]g) to resolve difficulty if any, in enacting the State legislation expeditiously before cut off date i.e. 23rd December, 1997, and; (b) the Committee of the Chief Ministers to examine the issues ragardihg devolution of powers, functions and responsibilities upon the PRIs, and to re-commend measures to streamline the Panchayati Raj system.

National Highways

*316. SHRI V. RAJAN CHELLA-PPA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the total distance of the National Highways, State-wise; and

(b) the length of the roads which have two lanes and four lanes in order to avoid heavy traffls, State-wise? . .

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKAT-TRAMAN): (a) and (b) Total length of National Highway in the country, Statewise and details of 2-lane and 4-lane.

S.No	Name of States	Total Length (in Kms.)	4 Lane (in Kms.)	2 Lane (in Kms.)
1	2	3.	4	5
1.	Andhra Pradesh	2888	28	2500
2.	Arunachal Pradesh	330		20
3.	Assam	2296		1714
4.	Bihar	2547	15	1860
5.	Chandigarh	24	8	16
6.	Delhi	72	72	
7.	Goa	229		107